

[2024] 2 एससीआर 776: 2024 आईएनएससी 143

शैलेश कुमार

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

(2012 की आपराधिक अपील संख्या 684)

26 फ़रवरी 2024

[एम. एम. सुंदरेश* और एस.वी.एन. भट्टी,जे.जे.]

विचार के लिए मुद्दा

विवेचना का उद्देश्य क्या है और विवेचना अधिकारी की भूमिका क्या है; क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 और 161 और सीआरपीसी धारा 172 को एक दूसरे के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए; क्या एफआईआर दर्ज होने से पहले जनरल डायरी एंट्री हो सकती है।

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - विवेचना का उद्देश्य और विवेचना अधिकारी की भूमिका:

अवधारित: एक अपराध की विवेचना एक अपराध की परिस्थितियों के पुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण में प्रासंगिक पुरुषों और सामग्रियों की एक वैध खोज है जो प्रतिबद्ध है - साक्ष्य कब्जे में, एक विवेचना अधिकारी समय में वापस यात्रा करेगा और इसलिए, विवेचना के तहत घटना की घटना के सही समय और तारीख तक पहुंचने के लिए समय क्षेत्र को बंद कर देगा - विवेचना का लक्ष्य उस सच्चाई का निर्धारण करना है जो होगा नामित अभियुक्त या संदिग्ध की दोषिता पर सही राय बनाने के लिए विवेचना अधिकारी की मदद करना - एक बार विवेचना में एकत्र किए गए सबूतों के निष्पक्ष मूल्यांकन पर इस तरह की राय बनने के बाद, अदालत की भूमिका तब सामने आती है जब साक्ष्य यानी मौखिक, दस्तावेजी, परिस्थितिजन्य,

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

वैज्ञानिक, इलेक्ट्रॉनिक आदि अभियोजन पक्ष के लिए और उसकी ओर से प्रस्तुत किए जाते हैं - पूरे नाटक के दौरान, साक्ष्य के नियमों का सम्मान किया जाना चाहिए, उचित प्रक्रिया के माध्यम से निष्पक्षता के तत्व के साथ छिड़का जाना चाहिए - हर धारणा को चुनौती देने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए - आपराधिक न्याय का प्रशासन उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध का निर्धारण करने में निहित है - एक अभियुक्त पर मुकदमा चलाने की राज्य की शक्ति विवेचना, साक्ष्य एकत्र करने और स्वीकृति के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने से शुरू होती है। [पैरा 17]

*रचयिता

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - साक्ष्य अधिनियम, 1872 - सीआरपीसी की धारा 172 के तहत केस डायरी का रखरखाव और साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 और धारा 161 - सीआरपीसी की धारा 172 और धारा 145 और 161 के आवेदन को सीआरपीसी की धारा 172 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त सीमित अधिकार के अधीन एक दूसरे के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए:

अवधारित: विवेचना की दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही में प्रवेश करने के उद्देश्य से एक विवेचना अधिकारी द्वारा अपनी विवेचना के दौरान एक केस डायरी रखी जाती है - ऐसा करते समय, विवेचना अधिकारी को अनिवार्य रूप से विवेचना के दौरान एकत्र किए गए आवश्यक विवरणों को प्रासंगिक तिथि, समय और स्थान के साथ रिकॉर्ड करना चाहिए - सीआरपीसी की धारा 172 की उप-धारा (1-ए) और (1-बी) के तहत, विवेचना अधिकारी को अपनी केस डायरी में, विवेचना के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान का उल्लेख उचित पृष्ठांकन के साथ करना होगा - इन उप-धाराओं का उद्देश्य निष्पक्ष विवेचना की सुविधा प्रदान करना है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए बयान पर सीआरपीसी की धारा 162 द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर किए जाने की अपेक्षित नहीं है - जब एक पुलिस अधिकारी अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए केस डायरी का उपयोग करता है, एक

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

अभियुक्त को स्वतः ही पुलिस अधिकारी की डायरी में दर्ज पूर्व बयान के उस हिस्से को पढ़ने का अधिकार मिलता है, जैसा कि सीआरपीसी के साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 या धारा 161 का सहारा लेते हुए हो सकता है - सीआरपीसी की धारा 172 (3) साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 और धारा 161 का विशिष्ट संदर्भ देती है - इसलिए, जब भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 या धारा 161 के तहत कोई मामला बनता है, सीआरपीसी की धारा 172 (3) के लाभ के साथ उसके तहत प्रदत्त लाभ एक अभियुक्त को दिया जाना है - इस प्रकार, जब भी पुलिस अधिकारी अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए इसका उपयोग करता है तब अभियुक्त को केस डायरी में की गई रिकॉर्डिंग के रूप में एक पुलिस अधिकारी से जिरह करने का अधिकार है, - हालांकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 161 अकेले केस डायरी का अवलोकन करके स्मृति को ताज़ा करने के मामले तक सीमित नहीं है, ऐसा करने के लिए कोई प्रतिबंधित नहीं है - इसी तरह, ऐसे मामले में जहां अदालत एक पुलिस अधिकारी के बयान का खंडन करने के उद्देश्य से केस डायरी का उपयोग करती है, तो एक अभियुक्त उक्त बयान को पढ़ने का हकदार है जो प्रासंगिक है, और उस आधार पर पुलिस अधिकारी से जिरह करें - ऐसे मामले में जो प्रासंगिक है वह विरोधाभास के उद्देश्य से इसका उपयोग करने की प्रक्रिया है न कि निष्कर्ष - स्थिति बनाने के लिए स्पष्ट, हालांकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 आर/डब्ल्यू एस.161 एक अभियुक्त सहित एक पक्ष के अधिकार से संबंधित है, ऐसा अधिकार सीमित और प्रतिबंधात्मक है जब इसे सीआरपीसी की धारा 172 पर लागू किया जाता है - यह कहना पर्याप्त है, कि उक्त अधिकार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है जब केस डायरी का लेखक अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए इसका उपयोग करता है या अदालत विरोधाभास के उद्देश्य से इसका उपयोग करती है - इसलिए, यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि एक ओर साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 और धारा 161 और दूसरी ओर सीआरपीसी की धारा 172 (3) को एक दूसरे के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए, जो सीआरपीसी की धारा 172 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त सीमित अधिकार के अधीन है। [पैरा 20, 26, 27]

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - केस डायरी की तुलना में प्रथम सूचना रिपोर्ट:

अवधारित: ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक संज्ञेय अपराध के कृत्य का खुलासा करने वाली सूचना पहले पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा रखी गई पुस्तक में दर्ज की जाएगी, न कि सामान्य डायरी में - एक सामान्य डायरी प्रविष्टि एफआईआर के पंजीकरण से पहले नहीं हो सकती है, उन मामलों को छोड़कर जहां प्रारंभिक विवेचना की आवश्यकता है - जबकि एक संज्ञेय अपराध के कृत्य का खुलासा करने वाली सूचना पर एक प्राथमिकी दर्ज की जानी है, इसलिए उसके बाद केस डायरी में एक रिकॉर्डिंग भी की जानी आवश्यक है। [पैरा 28]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 165 - प्रश्न पूछने या प्रस्तुत करना का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति:

अवधारित: साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 मुकदमे के दौरान सवाल पूछने और दस्तावेजों को पेश करने का आदेश देने की अदालत की शक्ति की बात करती है - यह सच्चाई की तलाश में अदालत को दी गई एक सामान्य और सर्वव्यापी शक्ति है - इस तरह की शक्ति का प्रयोग किसी भी गवाह के खिलाफ किया जाना है, दोनों में एक नागरिक और साथ ही एक आपराधिक मामले में - उद्देश्य एक प्रासंगिक के पर्याप्त प्रमाण की खोज करना है तथ्य और, इसलिए, उस प्रयोजन के लिए, न्यायाधीश अपनी पसंद का कोई भी प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत और सशक्त है - जब इस तरह की शक्ति का प्रयोग अदालत द्वारा किया जाता है, तो कोई भी संबंधित अधिकार नहीं है जिसे किसी पक्ष को उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दिए गए उत्तर पर किसी गवाह से जिरह करने के लिए बढ़ाया जा सकता है, सिवाय इसकी अनुमति के साथ। [पैरा 29]

दंड संहिता, 1860 - धारा 302 - अभियोजन पक्ष का मामला कि पीड़ित PW-2 और PW -3 के साथ पिकनिक पर गया था - उनकी वापसी पर, उन्हें अपीलकर्ता द्वारा चाकू से रोक दिया गया था, जिसने पीड़ित की छाती और पेट पर दो घातक वार किए थे - अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

अपराध को मुख्य दोषितासाबित करने के लिए(ए) मृत्यु पूर्व बयान, (बी) चश्मदीद गवाह, (सी) वसूली और (डी) अपराध के दृश्य के करीब अपीलकर्ता की कथित गिरफ्तारी - ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई - उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की - औचित्य:

अवधारित:पीड़ित-मृतक की पहली बार PW-5 (जो अस्पताल में काम कर रहा था) द्वारा परीक्षण की गई थी - PW-5 के समक्ष PW-1 (मृतक के पिता) की उपस्थिति बेहद संदिग्ध है -PW-5 द्वारा उसकी उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं बताई गई थी - PW-1 का साक्ष्य काफी अप्राकृतिक है क्योंकि उसने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान में मकसद के बारे में नहीं कहा है, न ही तथाकथित मृत्युकालीन घोषणा के बारे में जो PW-5 द्वारा भी नहीं देखी गई थी - PW-5 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक बहुत गंभीर स्थिति में था, खून बह रहा था और इसलिए, वह पर्याप्त उपचार नहीं दे सका - मृतक को तुरंत दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया - PW -1 की गवाही भी PW-3 और PW-8 (दूसरे अस्पताल में मृतक की परीक्षण करने वाले डॉक्टर) के विरोधाभासी है - इसी प्रकार, PW-2 और PW-3 के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, PW-2 की परीक्षणPW-11 (विवेचना अधिकारी) द्वारा 2 सप्ताह से अधिक समय तक नहीं की गई थी, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था - इस गवाह ने यह भी कहा कि वह मृतक का दोस्त नहीं था, इसलिए, घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति एक गंभीर संदेह पैदा करती है कि वह पिकनिक स्थल - PW-3 में मृतक के साथ उपस्थिति कैसे था, हालांकि मृतक के साथ था, उसके बाद उपस्थित नहीं था, जैसा कि PW-5 द्वारा गवाही दी गई थी और मृतक को दूसरे अस्पताल में भर्ती नहीं किया था जैसा कि PW -8 द्वारा बयान दिया गया था - अभियोजन पक्ष ने वाहन के चालक की परीक्षण करने के लिए नहीं चुना है यानी टेम्पो जिसमें मृतक को अस्पताल लेजाया गया था - इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि PW -9-विभिन्न क्षेत्राधिकार के एक अन्य पुलिस अधिकारी ने पूछताछ रिपोर्ट कैसे लिखी - इसके अलावा, PW -6 के लिए घटना स्थल

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

तक पहुंचना पूरी तरह से अविश्वसनीय है - PW -7 के उदाहरण पर अभियुक्त की गिरफ्तारी अभियोजन पक्ष द्वारा मामला बनाने की कोशिश करने का एक और उदाहरण है - यह समझ से बाहर है कि अपीलकर्ता घटना के स्थान पर मौजूद होगा जब वह भागने का प्रयास कर रहा है - इसी तरह का तर्क चाकू की बरामदगी के लिए किया जाता है, यह एक खुली जगह पर पाया गया था - केस डायरी के अवलोकन पर, यह पाया गया कि विभिन्न सुधार किए गए थे, जबकि कुछ पृष्ठ गायब भी थे - एक स्पष्ट प्रयास किया गया है तारीखों को सही करने का - जब ट्रायल कोर्ट ने केस डायरी का अवलोकन पुलिस अधिकारी के बयान का खंडन करने के उद्देश्य से किया, तो अपीलकर्ता पर जिम्मेदारी निर्धारित नहीं करनी चाहिए थी सीआरपीसी की धारा 172 (3) आर/डब्ल्यूएस 145 या धारा 161 के तहत यह अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है। जैसा भी मामला हो, साक्ष्य अधिनियम - चर्चा किए गए इन पहलुओं पर उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया था - इस प्रकार, अपीलकर्ता ने बरी करने का मामला बनाया है। [पैरा 32-39]

केस लॉ का हवाला

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य, [\[2013\] 14 एससीआर 713](#) : (2014) 2 एससीसी 1 - का पालन किया।

अरविंद कुमार @ नेमीचंद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, [\[2021\] 11 एससीआर 237](#); कॉमन कॉज और अन्य बनाम भारत संघ, [\[2015\] 6 एससीआर 731](#) : (2015) 6 एससीसी 332; भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त, [\[1983\] 3 एससीआर 109](#); (1983) 3 एससीसी 344; बालेश्वर मंडल बनाम बिहार राज्य, (1997) 7 एससीसी 219; बालकृष्ण बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, [\[2017\] 5 एससीआर 367](#); (2017) 7 एससीसी 668; राम चंदर बनाम हरियाणा राज्य, [\[1981\] 3 एससीआर 12](#) : (1981) 3 एससीसी 191 - पर भरोसा।

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

मनोज और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, [\[2022\] 9](#)

[एससीआर 452](#): (2023) 2 एससीसी 353 - संदर्भित।

उद्धृत पुस्तकें और पत्रिकाएं

भारत के विधि आयोग की एक सौ चौवनवीं रिपोर्ट (154 वाँ)।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।

खोजशब्दों की सूची

तहकीकात; विवेचना का लक्ष्य; विवेचना अधिकारी की भूमिका; केस डायरी; केस डायरी का रखरखाव; लिखित रूप में पिछले बयानों के रूप में जिरह करना; स्मृति को ताज़ा करने के लिए उपयोग की जाने वाली केस डायरी के रूप में जिरह करने के लिए अभियुक्त का अधिकार; केस डायरी का अवलोकन करते हुए स्मृति को ताज़ा करना; केस डायरी का उपयोग करके पुलिस अधिकारी का विरोधाभास; केस डायरी के संबंध में एफ.आई.आर. प्रश्न पूछने की न्यायाधीश की शक्ति।

से उत्पन्न मामला

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2012 की आपराधिक अपील संख्या 684।

उच्च न्यायालय के दिनांक 15.11.2010 के निर्णय और आदेश से 2001 की सीआरएलए संख्या 888 में नैनीताल में उत्तराखंड

पार्टियों के लिए दिखावे

मैसर्स डीपी सिंह, विक्रम सिंह, अमित गुप्ता, अर्चित सिंह, मनु मिश्रा, सुश्री श्रेया दत्त। कं मिटर और मिटर, अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट सौरभ त्रिवेदी, आशुतोष कुमार शर्मा, प्रतिवादी के लिए एडवोकेट।

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

जजमेंट

एम. एम. सुंदरेश, जे.

1. भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आईपीसी"के रूप में संदर्भित) की धारा 302 के तहत एसटी 166/1992 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार विरोधी यूपी (पूर्व) देहरादून द्वारा दोषी ठहराए गए अपीलकर्ता को आजीवन कारावास के लिए दोषी ठहराया गया है, जैसा कि 2001 की आपराधिक अपील संख्या 888 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि की गई है।
2. अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री डीपी सिंह और प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री सौरभ त्रिवेदी को सुना। हमने अपने सामने रखे गए पूरे रिकॉर्ड का अवलोकन किया है, और प्रस्तुत सारांश नोट्स पर उचित ध्यान दिया है।

संक्षिप्त तथ्य

3. मृतक, गजेंद्र सिंह अपने दो दोस्तों सुरेश (PW-2) और सुनील मंडल (PW-3) के साथ 21.06.1992 को सुबह लगभग 11 बजे पिकनिक मनाने गया था। लौटने पर, उन्हें मोटरसाइकिल पर सवार अपीलकर्ता द्वारा रोका गया। अपीलकर्ता ने "आज मैं आपका पूरा बकाया चुकाऊंगा"शब्द बोलकर मृतक गजेंद्र सिंह पर चाकू से हमला किया, जिससे क्रमशः छाती और पेट पर दो घातक वार किए गए। हमले का मकसद अपीलकर्ता द्वारा काम पूरा करने में विफलता प्रतीत होता है जिसके लिए मृतक ने 500/- रुपये की राशि दी।
4. PW-2 और PW-3 मृतक को उस अस्पताल में ले गए, जिसमें PW-5 काम कर रहा था, जिसके ड्राइवर की परीक्षण नहीं की गई है। मृतक को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद, PW-2 यात्रा करके मृतक के घर गया, जिसमें उसे 15 मिनट लगे, और मृतक पर हमले की सूचना उसके पिता, PW-1 को दे

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

दी। परिक्षण करने पर, PW -5 ने पाया कि मृतक गंभीर स्थिति में था और इसलिए, केवल प्राथमिक उपचार दिया और मृतक को देहरादून के एक अस्पताल में रेफर कर दिया। अस्पताल पहुंचने के बाद, PW-1 ने मृतक के साथ पूछताछ की, जिसने घटना का वर्णन करते हुए मृत्युकालीन घोषणा दी। PW -5 ने किसी भी गवाह की उपस्थिति के बारे में बात नहीं की, सिवाय इस तथ्य के कि मृतक को PW -3 द्वारा भर्ती कराया गया था और इसलिए, PW -1 को दिए गए उक्त मृत्युकालीन बयान का उल्लेख नहीं किया। PW -1 ने शिकायत किसी श्री इंदर सिंह (परिक्षण नहीं की गई) को डिकेट की और अस्पताल के ठीक सामने स्थित पुलिस स्टेशन गया। PW -1 की ओर से उपरोक्त कार्रवाई से पहले, PW -5 ने आपातकालीन चिकित्सा रजिस्टर में एक प्रविष्टि की थी जिसे बाद में डॉ बीवी शर्मा नामक एक अन्य व्यक्ति द्वारा भरा गया था (परिक्षण नहीं की गई)। डॉ. बीवी शर्मा ने तुरंत थाने में रिपोर्ट भेजी।

5. इससे पहले कि PW-1 पुलिस स्टेशन पहुंच पाता, अस्पताल से रिपोर्ट पहुंच गई थी और इसलिए विवेचना शुरू कर दी गई। हालांकि, न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी और न ही सामान्य डायरी में टिप्पणी की गई थी। वास्तव में, सामान्य डायरी पर उपलब्ध नोटिंग में, 21.06.1992 को किए गए किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया गया था, जैसा की अदालत के समक्ष PW -13 के बयान के अनुसार पेश किया था।
6. PW-2 और PW-3 मृतक को PW-1 और PW-2 के संस्करण के अनुसार देहरादून के नजदीकी अस्पताल में ले गए, जबकि PW-3 ने कहा कि यह वह खुद और PW-1 ने ही उक्त कवायद की थी। PW -8 के संस्करण के अनुसार, देहरादून अस्पताल में मृतक का इलाज करने वाले डॉक्टर को मृतक को उसके भाई श्री भूपेंद्र सिंह (परिक्षण नहीं) द्वारा अस्पताल लाया गया था।
7. PW -11 ने विवेचना शुरू की। वह घटना स्थल पर गया, स्केच बनाया और साइट प्लान तैयार किया। लौटते समय मृतक के एक अन्य भाई PW -7 ने

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

उसे बताया कि उसे सूचना मिली है कि अपीलकर्ता देहरादून भागने की कोशिश कर रहा है। PW 6, जिसने घटना के बारे में सुना, जिज्ञासा से घटना स्थल पर गया। अपीलकर्ता को PW -6, PW -7 और एक श्री संजीव सैनी (परिक्षण नहीं) की उपस्थिति में PW -11 द्वारा घटना के स्थान से लगभग 50-60 गज की दूरी पर पाया गया और गिरफ्तार किया गया। जिस चाकू का इस्तेमाल अपराध करने के लिए किया गया था, उसे घटना स्थल के पास लगभग 50 कदम पर एक खुली जगह से बरामद किया गया था। कोई गिरफ्तारी जापन तैयार नहीं किया गया है, हालांकि सामान्य डायरी में एक प्रविष्टि की गई थी। रिकवरी मेमो पर अकेले PW-6 और PW-7 द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

8. PW -4 डॉ. जयदीप दत्ता द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप दो बड़ी चोटों का संकेत मिला। PW -9, एक अलग क्षेत्राधिकार के पुलिस अधिकारी होने के नाते, विवेचना रिपोर्ट तैयार की, संभवतः इस आधार पर कि अंतिम मृत्यु वहीं हुई, क्योंकि दूसरा अस्पताल उसके अधिकार क्षेत्र में स्थित था।
9. PW-11 द्वारा प्रारंभिक विवेचना के बाद, PW-12 ने आगे की विवेचना अपने हाथ में ले ली, लेकिन गवाहों द्वारा दिए गए पहले के बयानों की जांच और सत्यापन के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरती। कुछ गवाहों की जल्द से जल्द जांच की गई है जबकि अन्य जैसे PW -2, PW -6 और PW -7 की जांच 2 सप्ताह बाद की गई थी। एफआईआर को डाक द्वारा भेजा गया था और इसलिए, उसके कुछ दिनों बाद क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट तक पहुंच गया।
10. मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों से पूछताछ की। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "सीआरपीसी" के रूप में संदर्भित) की धारा 313 के तहत की गई पूछताछ में, अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया। अपीलकर्ता की ओर से किए गए अनुरोध पर, सामान्य डायरी को ट्रायल कोर्ट द्वारा बुलाया गया

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

और उसका अवलोकन किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपादित कहानी पर एक सवाल उठाया गया था जो घटना की तारीख और समय तक जाता है। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि तारीखों के विशेष संदर्भ में कुछ इंटरपोलेशन थे और कुछ पृष्ठ गायब थे और गड़बड़ थे। यह निष्कर्ष देते हुए कि तारीख को 22.06.1992 के रूप में नोट करना और उसके बाद इसे 21.06.1992 को एक लिपिकीय गलती के रूप में रद्द करना, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता पर दोष लगाया कि उसने किसी के साथ मिलकर ऐसा करने के लिए पैंतरेबाज़ी की, हालांकि उक्त सुधार केवल अभियोजन पक्ष के मामले में मदद कर सकता है।

11. अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए, ट्रायल कोर्ट ने PW-1 से PW-3 के साक्ष्य पर भारी भरोसा किया। आपातकालीन चिकित्सा रजिस्टर की विसंगतियों और PW-1, PW-2 और PW-3 के बयानों के बीच समय बीतने के कारण मामूली और प्राकृतिक या अनदेखी विसंगतियों के रूप में खारिज कर दिया गया था। दोपहिया वाहन की वसूली पर बहुत भरोसा किया गया है, हालांकि साइट योजना में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। गवाहों के बयान दर्ज करने में हुई देरी को भी हल्के में लिया गया। PW -1 के समक्ष दिए गए तथाकथित मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को स्वीकार कर लिया गया, जबकि PW -5 द्वारा स्पष्ट रूप से यह बयान दिया गया था कि मृतक के साथ रहने के दौरान कोई भी मौजूद नहीं था जब तक कि उसे दूसरे अस्पताल में नहीं भेजा गया।
12. उच्च न्यायालय ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और PW-1 से PW-3 की गवाही पर भरोसा करके ट्रायल कोर्ट के फैसले से सहमति व्यक्त की।

अपीलकर्ता का प्रस्तुतिकरण

13. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पीडब्ल्यू -1 के साक्ष्य को दोनों अदालतों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। अस्पताल की रिपोर्ट काफी पहले ही थाने पहुंच गई थी। जिस व्यक्ति को PW -1 ने शिकायत लिखवाई थी, उसकी जांच नहीं की गई है। मकसद के लिए कोई

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

सामग्री नहीं है और पीडब्ल्यू -1 की गवाही PW -3, PW -5 और PW -8 द्वारा दी गई गवाही के विपरीत है। इसी तरह, पीडब्ल्यू -2 की उपस्थिति बेहद संदिग्ध है क्योंकि उसके साक्ष्य हफ्तों बाद दर्ज किए गए थे। वह दूसरे अस्पताल में पीडब्ल्यू -3 द्वारा भी मौजूद नहीं पाया गया था, हालांकि पीडब्ल्यू -3 ने अन्यथा गवाही दी थी। इसलिए, PW -2 के साक्ष्य को भी छोड़ दिया जाना चाहिए था। उनका यह कथन कि यह PW -1 है और वह खुद मृतक को दूसरे अस्पताल में ले गया था, PW -8 की गवाही के मद्देनजर गलत पाया गया है। निचली अदालतों को PW -5 और PW-8 के साक्ष्य पर पर्याप्त भरोसा करना चाहिए था, जो डॉक्टर प्रासंगिक समय पर अस्पताल में भर्ती रूप से काम कर रहे थे। तथ्य यह है कि सूचना मिलने के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह पूर्व-दिनांकित थी। यह विवाद एक अलग पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट से भी मजबूत होता है यानी PW -9 द्वारा।

14. विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं देकर गंभीर त्रुटि की है कि केस डायरी में कोई समय, तारीख और पर्याप्त विवरण का उल्लेख नहीं किया गया था। सीआरपीसी की धारा 172 के साथ-साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद "साक्ष्य अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 145, 161 और 165 के पीछे के उद्देश्य और तर्क को दोनों अदालतों द्वारा स्पष्ट रूप से अनदेखा किया गया है। मकसद साबित नहीं हुआ है क्योंकि गवाहों ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयानों में इसके बारे में नहीं बताया है। यह पूरी तरह से असफल जांच का मामला है और इसलिए अपीलकर्ता बरी होने का हकदार है।

प्रतिवादी का प्रस्तुतीकरण

15. राज्य के विद्वान वकील ने वाहन की वसूली पर पर्याप्त निर्भरता रखी। यह कहा गया है कि माना जाता है कि वाहन अपीलकर्ता के पिता का था। यही

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

कारण है कि इसकी हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे अनुमति दी गई। दोनों अदालतों ने सही माना है कि घटना की तारीख से लेकर अदालत में गवाही दर्ज होने तक समय बीतने के मद्देनजर विसंगतियां होना तय है। PW -2 और PW -3 के पास अपीलकर्ता को फंसाने का कोई गुप्त मकसद या कारण नहीं था। PW -3 का बयान जल्द से जल्द दर्ज किया गया है। PW-9 द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में कुछ भी गलत नहीं है। चूंकि कोई विकृति नहीं है, इसलिए दोनों न्यायालयों द्वारा उनके निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य की सराहना किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विचार-विमर्श

16. दोनों पक्षों की तथ्यात्मक प्रस्तुतियों पर विचार करने से पहले, हम पहले कानून की स्थिति से निपटेंगे जो अपील पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक है।

विवेचना और विवेचना अधिकारी की भूमिका

17. एक अपराध की विवेचना एक अपराध की परिस्थितियों के पुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण में प्रासंगिक पुरुषों और सामग्रियों की एक वैध खोज है। सबूत के कब्जे के साथ, एक विवेचना अधिकारी समय में वापस यात्रा करेगा और इसलिए विवेचना के तहत घटना की घटना के सही समय और तारीख तक पहुंचने के लिए समय क्षेत्र को बंद कर देगा। विवेचना का लक्ष्य सच्चाई का निर्धारण करना है जो विवेचना अधिकारी को नामित आरोपी या संदिग्ध की दोषिता पर सही राय बनाने में मदद करेगा। एक बार जब विवेचना में एकत्र किए गए सबूतों के निष्पक्ष मूल्यांकन पर ऐसी राय बन जाती है, तो अदालत की भूमिका तब सामने आती है जब अभियोजन पक्ष के लिए और उसकी ओर से साक्ष्य यानी मौखिक, दस्तावेजी, परिस्थितिजन्य, वैज्ञानिक, इलेक्ट्रॉनिक आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। सच्चाई का निर्धारण करने की दिशा में अपनी यात्रा में, एक अदालत अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा निभाई जाने वाली संबंधित भूमिकाओं को स्वीकार करते हुए सक्रिय भूमिका

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

निभाएगी। पूरे नाटक के दौरान, साक्ष्य के नियमों का सम्मान किया जाना चाहिए, उचित प्रक्रिया के माध्यम से निष्पक्षता के तत्व के साथ छिड़का जाना चाहिए। हर धारणा को चुनौती देने के लिए पर्याप्त अवसर देने होंगे। आपराधिक न्याय का प्रशासन उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध का निर्धारण करने में निहित है। किसी अभियुक्त पर मुकदमा चलाने की राज्य की शक्ति जांच, साक्ष्य एकत्र करने और स्वीकृति के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने से शुरू होती है।

18. जांच एजेंसी, अभियोजक और बचाव पक्ष से उम्मीद की जाती है कि वे सच्चाई को समझने के लिए अदालत को पर्याप्त सहायता देंगे। चूंकि जांच एजेंसी को किसी अपराध की जांच करनी होती है, इसलिए उसका प्राथमिक कर्तव्य एकत्र की गई सामग्री के माध्यम से संभावित अपराधी का पता लगाना है। उक्त एजेंसी के लिए प्रत्येक सामग्री एकत्र करना संभव हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उसे उपलब्ध सामग्री के साथ अपनी राय बनानी होगी। ऐसी एजेंसी को किसी भी कीमत पर किसी को आरोपी बनाने की जरूरत नहीं है। अंततः यह अदालत को तय करना है कि अपराधी कौन है। [अरविन्द कुमार @ नेमीचंद एवं अन्यराजस्थान राज्य, \[2021\] 11 एससीआर 237,](#)

"निष्पक्ष, दोषपूर्ण, रंगीन जांच

40. लोक सेवक होने के नाते एक विवेचना अधिकारी से निष्पक्ष रूप से जांच करने की उम्मीद की जाती है। ऐसा करते समय, उनसे सही निष्कर्ष पर आने के लिए उपलब्ध सामग्रियों की तलाश करने की अपेक्षा की जाती है। वह एक अपराधी के खिलाफ अपराध से संबंधित है। यह अपराध है जिसकी वह जांच करता है। जब भी कोई मानव वध होता है, तो एक विवेचना अधिकारी से सभी पहलुओं को कवर करने की उम्मीद की जाती है और इस प्रक्रिया में, हमेशा यह ध्यान में रखा जाएगा कि क्या अपराध धारा 299 आईपीसी के तहत आएगा और धारा 300 आईपीसी के

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

तहत आएगा। दूसरे शब्दों में, यह संतुष्ट करना उसका प्राथमिक कर्तव्य है कि एक मामला गैर इरादतन मानव वध के तहत आएगा जो हत्या की श्रेणी नहीं है और फिर एक हत्या है। जब पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो, तो वह धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए मामला तैयार करने में अति उत्साही नहीं होगा। हमारा मानना है कि जांच अधिकारी के दिमाग में एक लचीले बदलाव की आवश्यकता है। आखिरकार, ऐसा अधिकारी न्यायालय का भी अधिकारी होता है और उसका कर्तव्य सच्चाई का पता लगाना और सही निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायालय की सहायता करना होता है। वह पीड़ित या आरोपी के पक्षों को नहीं जानता है, लेकिन केवल कानून द्वारा निर्देशित होना चाहिए और उसकी जांच में निष्पक्षता का प्रतीक होना चाहिए।

41. एक दोषपूर्ण जांच के बीच एक सूक्ष्म अंतर है, और एक गणना और जानबूझकर कार्रवाई या निष्क्रियता द्वारा सामने लाया गया। एक दोषपूर्ण जांच अपने आप में अभियुक्त के लाभ के लिए तब तक लागू नहीं होगी, जब तक कि यह अभियोजन के मौलिक प्रकृति के मामले की जड़ में न जाए। दोषपूर्ण जांच से निपटने के दौरान, कानून की अदालत से अपेक्षा की जाती है कि वह उपलब्ध सबूतों की जांच करे और इस सिद्धांत पर सच्चाई का पता लगाए कि हर मामले में सच्चाई की ओर एक यात्रा शामिल है। अभियोजन पक्ष या अदालत द्वारा कोई पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण नहीं होगा क्योंकि एक मामले में नैतिकता के बजाय कानून का एक तत्व शामिल है।

XXX XXX XXX

44. हम केवल कुमार बनाम राज्य, (2018) 7 एससीसी 536 के निम्नलिखित निर्णय के माध्यम से निष्पक्ष जांच के लिए पूर्वोक्त सिद्धांत को दोहराएंगे:

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

"27. मामले को आगे बढ़ाने में विवेचना प्राधिकारी की कार्रवाई जिस तरह से उन्होंने की है, उसे फटकार लगाई जानी चाहिए। इस पहलू पर उच्च न्यायालय ने सही नोटिस किया कि पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तारी को उन कारणों से विफल कर दिया है जो उन्हें ही बेहतर पता है। यद्यपि हम प्रभु बनाम किंग सम्राट [प्रभु बनाम किंग एम्परर, एआईआर 1944 पीसी 73] में निर्धारित अनुपात से अवगत हैं, जिसमें न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि गिरफ्तारी की अनियमितता और अवैधता अपराध की दोषीता को प्रभावित नहीं करेगी यदि यह ठोस साक्ष्य द्वारा साबित हो जाता है, फिर भी इस मामले में, इस तरह की अनियमितता को सम्मान दिखाया जाना चाहिए क्योंकि विवेचना अधिकारी तथ्यों को दबाने के लिए जिम्मेदार हैं।

28. आपराधिक न्याय तिरस्कार से ऊपर होना चाहिए। यह अप्रासंगिक है कि क्या झूठ गवाहों के बयान में निहित है या अभियुक्त के अपराध में। विवेचना प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष तरीके से जांच करे और सच्चाई सामने लाए। पुनरावृत्ति की कीमत पर, मैं संबंधित अधिकारियों को अंतिम परिणाम की परवाह किए बिना निष्पक्ष तरीके से जांच करने के लिए याद दिलाना चाहूंगा। इस मामले में, जो कुछ हुआ है, हम अपनी आँखें बंद नहीं कर सकते; अपराध बोध या सबूतों की दृढ़ता के बावजूद, जिस पहलू पर पुलिस ने तथ्यों को दबाने के लिए सक्रिय रूप से मिलीभगत की है, उसे अनदेखा या अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

45. एक निष्पक्ष जांच तब रंगीन हो जाएगी जब इसमें दमन शामिल हो। आरोप-प्रत्यारोप को संशोधित करने या बदलने के प्रभाव वाले मकसद, चोटों और अन्य मौजूदा कारकों को दबाना एक लापरवाह जांच होगी और इसलिए, एक झूठी कथा बन जाएगी। यदि अदालतों को लगता है कि अभियोजन पक्ष के मामले की नींव झूठी है और एक सचेत दमन के खिलाफ निष्पक्षता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं होगी, तो अभियोजन पक्ष का बहुत मामला जमीन पर गिर जाता है जब तक कि एक अलग आरोप पर सजा देने के लिए निष्कर्ष पर आने के लिए अचूक सबूत न हों।

(महत्त्व सन्निविष्ट)

19. कॉमन कॉज और अन्य बनाम भारत संघ, (2015) 6 एससीसी 332,

"31. एक विवेचना एजेंसी पर यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत उच्च स्तर की जिम्मेदारी रखी जाती है कि एक निर्दोष व्यक्ति आपराधिक मुकदमे के अधीन न हो। इस जिम्मेदारी को एक विवेचना अधिकारी या एक विवेचना एजेंसी के लिए आवश्यक नैतिक ईमानदारी के समान उच्च स्तर के साथ जोड़ा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विवेचना बिना किसी पूर्वाग्रह के की जाती है और न केवल आरोपी व्यक्ति के लिए बल्कि किसी भी अपराध के पीड़ित के लिए भी सभी निष्पक्षता में अवधारित की जाती है, चाहे पीड़ित व्यक्ति हो या राज्य।

केस डायरी

सीआरपीसी की धारा 172

"172. अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी--(1) इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी प्रतिदिन किसी डायरी में अन्वेषण में अपनी कार्यवाहियों की प्रविष्टि करेगा

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

और उस समय, जिस समय उसने अपना अन्वेषण प्रारंभ किया और उसे बंद किया, उसके द्वारा देखे गए स्थान या स्थान तथा उसके अन्वेषण के माध्यम से सुनिश्चित परिस्थितियों का विवरण देते हुए।

(1-क) धारा 161 के तहत विवेचना के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान केस डायरी में डाले जाएंगे।

(1-ख) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट डायरी एक खंड और विधिवत पृष्ठांकित होगी।

(2) कोई भी आपराधिक न्यायालय ऐसे न्यायालय में जांच या विचारण के तहत किसी मामले की पुलिस डायरी भेज सकता है, और ऐसी डायरी का उपयोग मामले में सबूत के रूप में नहीं, बल्कि ऐसी जांच या परीक्षण में सहायता करने के लिए कर सकता है।

(3) न तो अभियुक्त और न ही उसके एजेंट ऐसी डायरियां मांगने के हकदार होंगे, न ही वह उन्हें केवल इसलिए देखने का हकदार होगा क्योंकि उन्हें न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया है; लेकिन, यदि उनका उपयोग उस पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसने उन्हें अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए बनाया है, या यदि न्यायालय ऐसे पुलिस अधिकारी का खंडन करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 161 या धारा 145, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 145

"145. पिछले वक्तव्यों के बारे में लिखित रूप में प्रतिपरीक्षा - किसी साक्षी की उसके द्वारा लिखित रूप में दिए गए पिछले कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी या लिखित रूप में कम की जा सकेगी और प्रश्नगत विषयों से सुसंगत होगी, ऐसे लेखन को उसे दिखाए बिना, या सिद्ध किए बिना; परंतु, यदि यह

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

लेखन द्वारा उसका खंडन करने का इरादा है, तो लेखन को साबित करने से पहले उसका ध्यान अवश्य होना चाहिए, इसके उन हिस्सों को बुलाया जाए जिनका उपयोग उसका खंडन करने के उद्देश्य से किया जाना है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 161

"161. स्मृति को ताज़ा करने के लिए प्रयुक्त लेखन के बारे में प्रतिकूल पक्ष का अधिकार--दो अंतिम पूर्ववर्ती धाराओं के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट कोई भी लेखन प्रस्तुत किया जाना चाहिए और प्रतिकूल पार्टी को दिखाया जाना चाहिए यदि उसे इसकी आवश्यकता है; ऐसा पक्षकार, यदि वह चाहे, तो गवाह की प्रतिपरीक्षा कर सकता है।

20. जांच की दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही में प्रवेश करने के उद्देश्य से एक जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच के दौरान एक केस डायरी रखी जाती है। ऐसा करते समय, विवेचना अधिकारी को विवेचना के दौरान एकत्र किए गए आवश्यक विवरणों को प्रासंगिक तारीख, समय और स्थान के साथ अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड करना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 172 की उपधारा (1-ए) और (1-बी) के तहत, विवेचना अधिकारी को अपनी केस डायरी में, विवेचना के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान का उल्लेख करना होगा। उप-धारा (1-ए) और (1-बी) 31/12/2009 से प्रभावी 2009 के अधिनियम 5 द्वारा डाले गए थे। इन उप-धाराओं का उद्देश्य निष्पक्ष विवेचना की सुविधा प्रदान करना है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए बयान पर सीआरपीसी की धारा 162 के अनुसार हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद नहीं है। इन उप-धाराओं की आवश्यकताओं का पालन करने के महत्व को उजागर करने के लिए, हम दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 पर भारत के विधि आयोग की एक सौ चौवनवीं रिपोर्ट (154 वीं) पर भरोसा करते हैं।

अध्याय IX,

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

"7. हमारे गंभीर विचार देने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कानून में पर्याप्त परिवर्तन करने की आवश्यकता के संबंध में सर्वसम्मति है, हम प्रस्ताव करते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों पर परिवर्तन होने चाहिए:

... इस प्रकार दर्ज किए गए बयान पर गवाह के हस्ताक्षर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, यदि गवाह की इच्छा है तो इस तरह दर्ज किए गए बयान की एक प्रति गवाह अभिस्वीकृति के तहत उसे सौंप दी जाएगी। जोर में बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए, धारा 172 में एक संबंधित संशोधन भी किया जाना चाहिए कि केस डायरी को बनाए रखने वाले विवेचना अधिकारी को इस प्रकार सुनिश्चित परिस्थितियों के विवरण के बारे में उल्लेख करना चाहिए, और प्रत्येक दिन के लिए डायरी के साथ संलग्न करना चाहिए, इस प्रकार सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज तथ्यों के बयान की प्रतियां भी संलग्न करनी चाहिए। न तो अभियुक्त और न ही उसका एजेंट ऐसी डायरी मांगने का हकदार होगा, जिसे धारा 172 सीआरपीसी के तहत सीमित उपयोग में लाया जा सकता है। संहिता के मौजूदा प्रावधानों के तहत, गवाह के बयान के सबसे पुराने रिकॉर्ड की तैयारी विवेचना अधिकारी के हाथों में छोड़ दी जाती है और धारा 162 में प्रदान की गई रिकॉर्डिंग की विधि के रूप में रिकॉर्ड की सटीकता सुनिश्चित नहीं करता है (यह सर्वविदित है कि अभियुक्त के इशारे पर कपटपूर्ण गलत प्रविष्टियों से कई अच्छे मामले खराब हो जाते हैं और यह भी सर्वविदित है कि कई निर्दोष व्यक्ति मुखबिर के पक्ष के इशारे पर दोषियों के साथ भेजे जाते हैं)....

(महत्त्व सन्निविष्ट)

21. उपर्युक्त सुझाव के आगे, भारत के विधि आयोग ने तदनुसार संसद के विचार के लिए सीआरपीसी की धारा 172 में एक मसौदा संशोधन प्रदान किया,

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

“... उपर्युक्त पंक्तियों पर, संबंधित धाराओं को निम्नानुसार संशोधित किया जा सकता है:

XXX XXX XXX

धारा 172(1) इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी प्रतिदिन अन्वेषण में अपनी कार्यवाहियों को एक डायरी में प्रविष्ट करेगा, जिसमें वह समय निर्धारित किया जाएगा जिस पर सूचना उस तक पहुंची, वह समय जिस पर उसने अपना अन्वेषण प्रारंभ किया और बंद किया, उसके द्वारा दौरा किया गया स्थान या स्थान और यदि उसके अन्वेषण के माध्यम से परिस्थितियाँ सुनिश्चित की गई हों तो विवरण; और प्रत्येक दिन के लिए डायरी में उस व्यक्ति या व्यक्तियों के संबंध में धारा 161 के तहत दर्ज किए गए तथ्यों के बयान की प्रतियां, यदि कोई हों, संलग्न करें, जिनकी परीक्षा उस दिन पूरी हुई थी।

(2) कोई भी आपराधिक न्यायालय ऐसे न्यायालय में जांच या विचारण के तहत किसी मामले की पुलिस डायरी भेज सकता है, और ऐसी डायरी का उपयोग मामले में सबूत के रूप में नहीं, बल्कि ऐसी जांच या मुकदमे में सहायता करने के लिए कर सकता है।

(3) न तो आरोपी और न ही उसके एजेंट ऐसी डायरियां मांगने के हकदार होंगे और न ही वह उन्हें सिर्फ इसलिए देखने के हकदार होंगे क्योंकि उन्हें इस न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया है।

(महत्त्व सन्निविष्ट)

22. जबकि यह विवेचना अधिकारी की जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि वह अपनी केस डायरी में उचित रिकॉर्डिंग करे, सीआरपीसी की धारा 172 की उप-धारा (3) के तहत अभियुक्त के लिए ऐसी डायरियों को पेश करने या उनका

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

अवलोकन करने का कोई अधिकार नहीं है, सिवाय उस मामले को छोड़कर जहां उनका उपयोग एक पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो उसकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए उनका उपयोग करता है। या ऐसे मामले में जहां अदालत पुलिस अधिकारी का खंडन करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है। ऐसे मामले में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 या धारा 161, जैसा भी मामला हो, का प्रावधान लागू होगा।

23. कानून बिल्कुल तय है कि विवेचना अधिकारी द्वारा केस डायरी का अनुचित रखरखाव अभियुक्त के लाभ के लिए नहीं होगा। किसी दिए गए मामले में सीआरपीसी की धारा 172 का पालन न करने के बावजूद अभियुक्त द्वारा पूर्वाग्रह दिखाया और साबित किया जाना है। हालांकि, यह पुलिस अधिकारी के इसे ठीक से बनाए रखने के लिए अनिवार्य कर्तव्य को दूर नहीं करता है। चूंकि अदालत सच्चाई का संरक्षक है, इसलिए यह विवेचना अधिकारी का कर्तव्य है कि वह अदालत को संतुष्ट करे जब वह उसका खंडन करना चाहता है। इसलिए, अभियुक्त का अधिकार बहुत प्रतिबंधात्मक और सीमित है।

भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त, (1983) 3 एससीसी 344,

"17. दूसरा निष्कर्ष जो हमें परेशान करता है, वह यह है कि पुलिस केस डायरी (रिकॉर्ड पर जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक में निर्धारित) की प्रविष्टियां उस ईमानदारी और दक्षता के साथ दर्ज नहीं की गई हैं, जिसकी कानून को ऐसे दस्तावेज के लिए आवश्यकता होती है। उस स्थिति के एक दस्तावेज का बेतरतीब रखरखाव न केवल इसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार लोगों को कोई श्रेय नहीं देता है, बल्कि उस उद्देश्य को पराजित करता है जिसके लिए इसे बनाए रखने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पुलिस केस डायरी में प्रविष्टियां तत्परता के साथ, पर्याप्त विस्तार से, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए, सावधानीपूर्वक कालानुक्रमिक क्रम में और पूरी निष्पक्षता के साथ की जानी चाहिए।

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

(महत्त्व सन्निविष्ट)

24. बालेश्वर मंडल वि. बिहार राज्य, (1997) 7 एससीसी 219,

"5. विवेचना से निपटने वाली बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 164 के साथ पठित धारा 172 सीआरपीसी के तहत, किसी अपराध की विवेचना करने वाले एक विवेचना अधिकारी को अपनी केस डायरी में दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही और जानकारी रिकॉर्ड करने का दायित्व है, और साइट प्लान और अन्य दस्तावेजों की तैयारी के अलावा, सूचना प्राप्त होने के समय और उसके द्वारा देखी गई जगह को भी रिकॉर्ड करना है। विवेचना अधिकारी को रासायनिक जांच के लिए घटना स्थल से जब्त किए गए खून से सने कपड़े और मिट्टी भेजने की भी आवश्यकता होती है। सीआरपीसी की धारा 172 के प्रावधानों का पालन करने में विवेचना अधिकारी की ओर से विफलता उसकी ओर से एक गंभीर चूक है जिसके परिणामस्वरूप उसकीविवेचना के मूल्य और विश्वसनीयता को कम किया गया है। इस मामले में विवेचना अधिकारी ने न तो डायरी में गवाहों के बयान दर्ज करने का समय दर्ज किया और न ही उन्होंने घटना स्थल से जब्त किए गए खून से सने कपड़े और मिट्टी को सीरोलॉजिस्ट द्वारा जांच के लिए भेजा। उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अनुपालन न करने में विवेचना अधिकारी की ओर से हुई चूक पर भी प्रतिकूल टिप्पणी की। इसलिए, हम यह मानते हैं कि, वास्तव में, मामले की विवेचना करते समय धारा 172 सीआरपीसी के जनादेश का पालन नहीं करने में विवेचनाअधिकारी की ओर से गंभीर चूक हुई थी, जिसने इस अपील को जन्म दिया है। लेकिन विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि क्या विवेचना अधिकारी द्वारा नियमों का पालन न करने से विचारण में अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है? सत्र न्यायालय और अपीलीय न्यायालय

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

के समक्ष रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य यह नहीं दर्शाते हैं कि रासायनिक जांच के लिए घटना स्थल से जब्त किए गए खून से सने कपड़े और मिट्टी को नहीं भेजने और डायरी में गवाहों के बयान दर्ज करने के समय को नोट नहीं करने में विवेचना अधिकारी की ओर से हुई चूक के परिणामस्वरूप अभियुक्त के बचाव के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। वर्तमान मामले में, घटना का स्थान और मृतक की पहचान विवादित नहीं है। इसके अलावा, चश्मदीद गवाहों की गवाही जो सुसंगत है और दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है, नीचे की दोनों अदालतों द्वारा विश्वास किया गया था। एक बार जब चश्मदीद गवाहों पर विश्वास कर लिया जाता है और अदालतें इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती हैं कि चश्मदीद गवाहों की गवाही विश्वसनीय है, तो धारा 172 सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन नहीं करने में विवेचना अधिकारी की ओर से चूक जब तक कि अभियुक्त के लिए कुछ पूर्वाग्रह नहीं दिखाया जाता है, अदालत द्वारा दर्ज अपराध के निष्कर्ष को प्रभावित नहीं करेगा। न तो उच्च न्यायालय और न ही इस न्यायालय के समक्ष यह बताया गया कि सीआरपीसी की धारा 172 के प्रावधानों और इस संबंध में बनाए गए नियमों का पालन न करने से अभियुक्त किस तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। इसलिए, हमारी राय है कि नीचे की अदालतों के फैसले विवेचना अधिकारी की ओर से रासायनिक परीक्षण के लिए घटना स्थल से जब्त की गई मिट्टी को नहीं भेजने या डायरी में गवाहों के बयानों की रिकॉर्डिंग के समय में प्रवेश नहीं करने की चूक के कारण प्रभावित नहीं होते हैं।

(महत्त्व सन्निविष्ट)

25. मनोज एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2023) 2 एससीसी 353,

"203. अध्याय XII के तहत सीआरपीसी की योजना

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

(ग) (पुलिस को सूचना और अन्वेषण करने की शक्तियाँ) स्पष्ट है - पुलिस के पास स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से विवेचना करने की शक्ति है; जिसके दौरान, एक डायरी रखना अनिवार्य है जहाँ दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही को घटनाओं के समय, दौरे किए गए स्थानों, प्रस्थान और वापस रिपोर्टिंग, दर्ज किए गए बयानों आदि के विशिष्ट उल्लेख के साथ रिकॉर्ड किया जाना है। जबकि आपराधिक अदालत को जांच या परीक्षण के उद्देश्य से धारा 172 (2) के तहत इन डायरियों को बुलाने का अधिकार है (और सबूत के रूप में नहीं), धारा 173 (3) यह स्पष्ट करती है कि अभियुक्त उन्हें पढ़ने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, जब तक कि पुलिस स्वयं इस पर भरोसा न करे (उनकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए) या यदि अदालत इसका उपयोग पुलिस अधिकारियों की गवाही का खंडन करने के लिए करती है। [मुकुंद लाल वि. भारत संघ, 1989 सप्प (1) एससीसी 622: 1989 एससीसी (सीआरआई) 606; मलकीयत सिंह वि. [पंजाब राज्य, (1991) 4 एससीसी 341: 1991 एससीसी (सीआरआई) 976]

204. मनु शर्मा में [मनु शर्मा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2010) 6 एससीसी 1: (2010) 2 एससीसी (सीआरआई) 1385], पुलिस डायरी के संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा कि "[टी] उसका उद्देश्य और उद्देश्य काफी स्पष्ट प्रतीत होता है कि जांच, पारदर्शिता में निष्पक्षता होनी चाहिए और उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए एक रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए"। यदि पुलिस पुलिस डायरी को सही ढंग से बनाए रखने में विफल रहती है तो यह उद्देश्य पूरी तरह से अर्थहीन हो जाता है। जांच के दौरान उठाए गए कदमों को सावधानीपूर्वक नोट करने में विफलता, और इसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता की कमी, आरोपी के निष्पक्ष जांच के अधिकार को कमजोर करती है; यह ट्रायल कोर्ट पर निर्भर करता

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

है कि वह अभियोजन पक्ष को स्वेच्छा से स्वीकार करने के बजाय रिकॉर्ड की व्यापक रूप से जांच करने में सक्रिय भूमिका निभाए, ताकि जांच के दौरान की गई ऐसी छिपी या छिपी हुई कार्रवाइयों को उजागर किया जा सके। [आपराधिक मुकदमे में अदालतों की भूमिका पर *जाहिरा हबीबुल्ला एच. शेख* बनाम भारत संघ में चर्चा की गई है। *गुजरात राज्य*, (2004) 4 एससीसी 158 2004 एससीसी (सीआरआई) 999।

(महत्त्व सन्निविष्ट)

26. जब एक पुलिस अधिकारी अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए केस डायरी का उपयोग करता है, तो एक अभियुक्त को स्वतः ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 या धारा 161, जैसा भी मामला हो, का सहारा लेकर पुलिस अधिकारी की डायरी में दर्ज पूर्व बयान के उस हिस्से को पढ़ने का अधिकार मिल जाता है।
27. सीआरपीसी की धारा 172 (3) साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 और धारा 161 का विशिष्ट संदर्भ देती है। इसलिए, जब भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 या धारा 161 के तहत कोई मामला बनता है, तो सीआरपीसी की धारा 172 (3) के लाभ के साथ-साथ उसके तहत प्रदत्त लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, अभियुक्त को केस डायरी में की गई रिकॉर्डिंग के रूप में एक पुलिस अधिकारी से जिरह करने का अधिकार है, जब भी पुलिस अधिकारी अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए इसका उपयोग करता है। यद्यपि साक्ष्य अधिनियम की धारा 161 केवल केस डायरी का अवलोकन करके स्मृति को ताज़ा करने के मामले तक ही सीमित नहीं है, ऐसा करने के लिए कोई अपवर्जन नहीं है। इसी तरह, ऐसे मामले में जहां अदालत एक पुलिस अधिकारी का खंडन करने के उद्देश्य से केस डायरी का उपयोग करती है, तो एक अभियुक्त को इस प्रकार दर्ज किए गए उक्त बयान का अवलोकन करने का अधिकार है जो प्रासंगिक है, और उस आधार पर पुलिस अधिकारी से जिरह करें। ऐसे मामले में जो प्रासंगिक है वह विरोधाभास के उद्देश्य से

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

इसका उपयोग करने की प्रक्रिया है न कि निष्कर्ष के लिए। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, हालांकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 161 के साथ पठित धारा 145 एक अभियुक्त सहित एक पक्ष के अधिकार से संबंधित है, ऐसा अधिकार सीमित और प्रतिबंधात्मक है जब इसे सीआरपीसी की धारा 172 पर लागू किया जाता है। विरोधाभास का। इसलिए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि एक तरफ साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 और धारा 161 और दूसरी तरफ सीआरपीसी की धारा 172 (3) को सीआरपीसी की धारा 172 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त सीमित अधिकार के अधीन एक दूसरे के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए। बालक्रम बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, (2017) 7 एससीसी 668,

"9. उपर्युक्त प्रावधानों को संयुक्त रूप से और समरूप रूप से पढ़ा जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 172 की उपधारा (2) से यह स्पष्ट है कि ट्रायल कोर्ट के पास विवेचना अधिकारी द्वारा रखी गई पुलिस डायरी में प्रविष्टियों को मंगाने और उनकी विवेचना करने की निरंकुश शक्ति है। यह बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय है। विधायिका ने उस न्यायालय पर पूरा भरोसा जताया है जो जांच या परीक्षण कर रहा है। यदि साक्ष्य में कोई असंगति या विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो न्यायालय सीआरपीसी की धारा 172 की उप-धारा (3) में प्रदान किए गए पुलिस अधिकारी का खंडन करने के उद्देश्यों के लिए डायरी में की गई प्रविष्टियों का उपयोग कर सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मामले की सुनवाई करने वाला न्यायालय न्याय के हित का सबसे अच्छा संरक्षक है। उप-धारा (2) के तहत आपराधिक अदालत डायरी भेज सकती है और उन्हें सबूत के रूप में नहीं, बल्कि जांच या मुकदमे में सहायता के लिए उपयोग कर सकती है। ऐसी डायरियों में प्रविष्टियों से न्यायालय को जो जानकारी मिल सकती है, उसका उपयोग आमतौर पर पुलिस

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

गवाह से पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए आधार के रूप में किया जाएगा और अदालत अपने विवेक से प्रविष्टियों का उपयोग पुलिस अधिकारी का खंडन करने के लिए कर सकती है, जिसने उन्हें बनाया था। लेकिन पुलिस डायरी में प्रविष्टियां न तो ठोस हैं और न ही पुष्ट साक्ष्य हैं, और उनका उपयोग पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य गवाह के खिलाफ नहीं किया जा सकता है, वह भी ऊपर बताए गए सीमित सीमा तक।

10. अभियुक्त द्वारा पुलिस डायरी के उपयोग पर आते हुए, धारा 172 की उप-धारा (3) स्पष्ट रूप से कहती है कि न तो अभियुक्त और न ही उसके एजेंट ऐसी डायरी मांगने के हकदार होंगे और न ही वह उन्हें केवल इसलिए देखने का हकदार हो सकता है क्योंकि उन्हें न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया है। लेकिन, यदि पुलिस अधिकारी डायरी में प्रविष्टियों का उपयोग अपनी स्मृतिको ताजा करने के लिए करता है या यदि न्यायालय ऐसे पुलिस अधिकारी का खंडन करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करता है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 और 161, जैसा भी मामला हो, के प्रावधान लागू होंगे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 में गवाह द्वारा लिखित रूप में दिए गए या लिखित रूप में दिए गए पिछले बयानों के बारे में प्रतिपरीक्षा करने का प्रावधान है और यदि इसका आशय लिखित रूप में उसका खंडन करना था, तो उसका ध्यान उन हिस्सों की ओर दिलाया जाना चाहिए जिनका उपयोग विरोधाभास के उद्देश्य से किया जाना है। धारा 161 स्मृति को ताजा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेखन के रूप में प्रतिकूल पक्ष के अधिकार से संबंधित है। इसलिए, यह देखा जा सकता है कि, पुलिस डायरी में प्रविष्टियों के संदर्भ में पुलिस अधिकारी से जिरह करने का अभियुक्त का अधिकार बहुत सीमित है और यहां तक कि सीमित दायरा केवल तभी उत्पन्न होता है जब न्यायालय पुलिस अधिकारी का खंडन करने के लिए

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

प्रविष्टियों का उपयोग करता है या जब पुलिस अधिकारी अपनी स्मृति को ताजा करने के लिए इसका उपयोग करता है।

11. दूसरे शब्दों में, यदि न्यायालय पुलिस अधिकारी का खंडन करने के उद्देश्य से ऐसी प्रविष्टियों का उपयोग नहीं करता है या यदि पुलिस अधिकारी अपनी स्मृति को ताजा करने के लिए इसका उपयोग नहीं करता है, तो अभियुक्त को उस सीमित सीमा तक भी प्रविष्टियों का उपयोग करने का कोई अधिकार मिलने का सवाल ही नहीं उठता। आरोपी व्यक्ति पुलिस डायरी में प्रविष्टियों का हवाला देकर अदालत में अपनी परीक्षा के दौरान पुलिस अधिकारी को अपनी स्मृति को ताजा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

12. साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 में दो अंग होते हैं। धारा 145 के पहले अंग में यह प्रावधान किया गया है कि एक गवाह को उसके द्वारा दिए गए पिछले बयानों के बारे में जिरह की जा सकती है, बिना उसे इस तरह के लेखन को दिखाए बिना। लेकिन दूसरा अंग यह प्रदान करता है कि, यदि लेखन द्वारा उसका खंडन करने का इरादा है, तो लिखने से पहले उसका ध्यान साबित किया जाना चाहिए, इसके उन हिस्सों को बुलाया जाना चाहिए जिनका उपयोग उसका खंडन करने के उद्देश्य से किया जाना है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 (3) और 145 एक ही मामले के विभिन्न पहलुओं से निपटती हैं और इसलिए, इसे एक साथ पढ़ा जाना चाहिए।

13. जैसा कि यह हो सकता है, जैसा कि उल्लेख किया गया है, पुलिस डायरी में प्रविष्टियों के संदर्भ में पुलिस अधिकारी से जिरह करने के अभियुक्त का अधिकार बहुत सीमित है और यहां तक कि सीमित दायरा केवल तब उत्पन्न होता है जब न्यायालय पुलिस अधिकारी का खंडन करने के लिए ऐसी प्रविष्टियों का

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)
उपयोग करता है या जब पुलिस अधिकारी अपनी स्मृति को ताजा करने के लिए इसका उपयोग करता है और वह फिर से धारा 145 और 161 के प्रावधानों के अधीन है। साक्ष्य अधिनियम। इस प्रकार, एक गवाह से उसके द्वारा दिए गए पिछले बयानों के रूप में प्रतिपरीक्षा की जा सकती है, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत विचार किया गया है, यदि इस तरह के पिछले बयानों को कानून के अनुसार, अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पर लाया जाता है और यदि धारा 172 (3) सीआरपीसी के तहत अपेक्षित आकस्मिकताएं पूरी होती हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 सीआरपीसी की धारा 172 के प्रावधानों को न तो विस्तारित करती है और न ही नियंत्रित करती है। हम यहां खुद को जोड़ने की जल्दी कर सकते हैं कि सीआरपीसी की धारा 172 में कोई गुंजाइश नहीं है कि अदालत, अभियोजन या अभियुक्त को पुलिस डायरी का उपयोग करने के लिए पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य गवाह का खंडन करने के उद्देश्य से सक्षम बनाया जा सके।

(महत्त्व सन्निविष्ट)

केस डायरी की तुलना में प्रथम सूचना रिपोर्ट

सीआरपीसी की धारा 154

"154. (1) संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना, यदि किसी पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो उसके द्वारा या उसके निदेश के अधीन लिखित रूप में कम की जाएगी और सूचनादाता को पढ़ी जाएगी; और ऐसी प्रत्येक सूचना, चाहे वह पूर्वोक्त रूप में लिखित रूप में दी गई हो या लिखित रूप में कम की गई हो, (ग) यदि हां, तो क्या यह पत्र देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

और उसका सार ऐसे अधिकारी द्वारा रखे जाने वाली पुस्तक में प्रविष्ट किया जाएगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे।

28. सीआरपीसी की धारा 154 के जनादेश में निहित है कि संज्ञेय अपराध के कृत्य का खुलासा करने वाली प्रत्येक जानकारी को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा रखे जाने वाले पुस्तक में दर्ज किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य, (2014) 2 एससीसी 1 में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या संज्ञेय अपराध के कृत्य का खुलासा करने वाली जानकारी को पहले सामान्य डायरी में दर्ज किया जाएगा या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा रखी गई पुस्तक में, जिसे आम बोलचाल में प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है, सीआरपीसी की धारा 154 और पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 44 के बीच परस्पर क्रिया का गंभीर विश्लेषण किया है। इस न्यायालय के पास उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए सीआरपीसी 1861, सीआरपीसी 1973 और पुलिस अधिनियम 1861 के विधायी इतिहास का विश्लेषण करने का भी अवसर था, जिसके तहत यह माना गया था कि एक संज्ञेय अपराध के अभियोग का खुलासा करने वाली सूचना को पहले पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा रखी गई पुस्तक में दर्ज किया जाएगा, न कि सामान्य डायरी में। इसलिए, यह पूरी तरह स्पष्ट है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले एक सामान्य डायरी प्रविष्टि नहीं हो सकती है, सिवाय उन मामलों के जहां प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है। जबकि एक संज्ञेय अपराध के कृत्य का खुलासा करने वाली सूचना पर एक प्राथमिकी दर्ज की जानी है, इसलिए केस डायरी में एक रिकॉर्डिंग भी की जानी आवश्यक है। ललिता कुमारी (सुप्रा),

"57. छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एसजी द्वारा यह संतुष्ट है कि "पुस्तक" में धारा 154 के तहत पहली सूचना की रिकॉर्डिंग सामान्य डायरी/स्टेशन डायरी/दैनिक डायरी में

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)
प्रविष्टि के बाद है, जिसे पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। इसलिए, विद्वान एसजी के अनुसार, पहली सूचना जनरल डायरी में जल्द से जल्द एक दस्तावेज है, फिर यदि किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है तो पुलिस अधिकारी इसे संचालित कर सकता है और उसके बाद सूचना एफआईआर के रूप में दर्ज की जाएगी। यह व्याख्या पूरी तरह से निराधार है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्तव में "सूचना" है जो समय के बिंदु पर सबसे पहले प्राप्त होती है, जिसे या तो लिखित रूप में दिया जाता है या लिखित रूप में कम कर दिया जाता है। यह इसका "पदार्थ" नहीं है, जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डायरी में दर्ज किया जाना है। शब्द "सामान्य डायरी" (जिसे कुछ राज्यों में "स्टेशन डायरी" या "दैनिक डायरी" भी कहा जाता है) संहिता की धारा 154 के तहत नहीं बल्कि उन राज्यों में पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 44 के प्रावधानों के तहत बनाए रखा जाता है जिन पर यह लागू होता है, या किसी राज्य पर लागू पुलिस अधिनियम (एस) के संबंधित प्रावधानों के तहत या किसी राज्य के पुलिस मैनुअल के तहत, जैसा भी मामला हो।

58. पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 44 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"44. पुलिस अधिकारियों का डायरी रखना-पुलिस थाने के भारसाधक प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सामान्य डायरी ऐसे प्रारूप में रखे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाए और उसमें अधिमान्य सभी शिकायतों और प्रभारों, गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के नाम, शिकायतकर्ताओं के नाम, अभिलिखित करे, उनके खिलाफ लगाए गए अपराध, हथियार या संपत्ति जो उनके कब्जे से या

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

अन्यथा ली गई होगी, और उन गवाहों के नाम जिनकी जांच की गई होगी। जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी डायरी मंगवाने और निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगा।

59. यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 1861 के दौरान, जब उपरोक्त पुलिस अधिनियम, 1861 पारित किया गया था, दंड प्रक्रिया संहिता, 1861 भी पारित की गई थी। उस संहिता की धारा 139 एफआईआर के पंजीकरण से संबंधित है और इस धारा में "डायरी" शब्द का भी उल्लेख किया गया है, जैसा कि इस धारा की भाषा से देखा जा सकता है, जैसा कि नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"139. शिकायत, आदि, लिखित रूप में होना- पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी गई प्रत्येक शिकायत या जानकारी को लिखित रूप में कम किया जाएगा, और उसके पदार्थ को ऐसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली डायरी में दर्ज किया जाएगा, ऐसे प्रारूप में जो स्थानीय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सरकार।

(महत्त्व सन्निविष्ट)

इस प्रकार, पुलिस अधिनियम, 1861 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1861, दोनों को एक ही वर्ष में पारित किया गया था, एक ही शब्द "डायरी" का उपयोग किया गया था।

60. हालाँकि, वर्ष 1872 में, एक नई संहिता पारित की गई जिसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1872 कहा जाता था। संहिता की धारा 112 एफआईआर दर्ज करने के मुद्दे से संबंधित है और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

"112. पुलिस को शिकायत लिखित रूप में दी जाएगी- किसी पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को दी गई प्रत्येक शिकायत को लिखित रूप में कम किया जाएगा, और उसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद या चिह्नित किया जाएगा, और उसका सार स्थानीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऐसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में दर्ज किया जाएगा। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1872 में, एक प्रस्थान किया गया था और "डायरी" के स्थान पर "पुस्तक" शब्द का उपयोग किया गया था। "पुस्तक" शब्द स्पष्ट रूप से एफआईआर बुक को संदर्भित करता है जिसे एफआईआर दर्ज करने के लिए संहिता के तहत रखा जाना है।

61. यह प्रश्न कि एफआईआर को एफआईआर बुक में दर्ज किया जाना है या जनरल डायरी में, अब यह अभिन्न नहीं है। इस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा पहले ही आधिकारिक रूप से निर्णय लिया जा चुका है।

62. में मधु बाला वि. सुरेश कुमार। मधु बाला वि. सुरेश कुमार. (1997) 8 एससीसी 476: 1998 एससीसी (सीआरआई) 1111. इस न्यायालय ने माना है कि एफआईआर रजिस्टर में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए जो 200 पृष्ठों की एक पुस्तक होगी। यह सच है कि जानकारी के पदार्थ का उल्लेख दैनिक डायरी (या सामान्य डायरी) में भी किया जाना है। लेकिन, बुनियादी आवश्यकता एफआईआर बुक या रजिस्टर में एफआईआर दर्ज करना है। यहां तक कि भजनलाल हरियाणा राज्य बनाम हरियाणा राज्य में। भजन लाल, 1992 सप्प (1) एससीसी 335: 1992 एससीसी (सीआरआई) 426 के मामले में, इस न्यायालय ने माना

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

कि एफआईआर को एक पुस्तक में एक ऐसे रूप में दर्ज किया जाना चाहिए जिसे आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है।

63. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एफआईआर का पंजीकरण एफआईआर बुक या एफआईआर रजिस्टर नामक पुस्तक में किया जाना है। निस्संदेह, इसके अतिरिक्त, संबंधित पुलिस अधिनियम अथवा नियमों में, जैसा भी मामला हो, संगत राज्य उपबंधों के अंतर्गत सामान्य डायरी में एफआईआर का सार अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट के सार का साथ-साथ उल्लेख किया जा सकता है।

64. जनरल डायरी एक पुलिस स्टेशन में होने वाले सभी महत्वपूर्ण लेनदेन/घटनाओं का रिकॉर्ड है, जिसमें पुलिस कर्मचारियों का प्रस्थान और आगमन, कार्यभार सौंपना या लेना, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, कानून और व्यवस्था कर्तव्यों का विवरण, वरिष्ठ अधिकारियों की यात्रा आदि शामिल हैं। यह इस संदर्भ में है कि पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा रही प्रत्येक एफआईआर का सार या पदार्थ का उल्लेख जनरल डायरी में भी किया गया है क्योंकि एफआईआर का पंजीकरण भी पुलिस स्टेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। चूंकि सामान्य डायरी एक रिकॉर्ड है जिसे दिन-प्रतिदिन के आधार पर कालानुक्रमिक रूप से बनाए रखा जाता है (प्रत्येक दिन, नए नंबर 1 से शुरू होता है), एफआईआर बुक में सामान्य डायरी प्रविष्टि संदर्भ का भी एक साथ उल्लेख किया जाता है, जबकि एफआईआर नंबर का उल्लेख सामान्य डायरी प्रविष्टि में किया जाता है क्योंकि ये दोनों एक साथ तैयार किए जाते हैं।

65. यह बताना प्रासंगिक है कि एफआईआर बुक को वार्षिक आधार पर दिए गए नंबर के साथ रखा जाता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक एफआईआर का एक विशिष्ट वार्षिक नंबर दिया गया है। यह अदालतों में दिए गए केस नंबरों के समान है। इस कारण

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

से, जहां भी आवश्यक हो, पर्यवेक्षी पुलिस अधिकारियों द्वारा और न्यायालयों द्वारा एफआईआर दर्ज करने पर सख्त नियंत्रण और ट्रैक रखना संभव है। प्रत्येक एफआईआर की कॉपी वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है।

66. दूसरी ओर, जनरल डायरी में प्रत्येक दिन की कार्यवाही के अन्य विवरणों की एक बड़ी संख्या होती है। सामान्य डायरी की प्रति पुलिस स्टेशन पर अधिकार क्षेत्र वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी जाती है, हालांकि इसकी प्रति एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भेजी जाती है। इस प्रकार, जनरल डायरी में दर्ज की गई प्रत्येक एफआईआर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और/या अदालत द्वारा सख्त नियंत्रण रखना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें उल्लिखित अन्य विवरणों की भारी मात्रा और हर दिन संख्या बदल रही है।

67. जब कभी पुलिस थाने में शिकायत दी जाती है तो एफआईआर बुक में शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। दूसरी ओर, सामान्य डायरी में शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, कभी-कभी, दी गई शिकायत में बड़ी संख्या में पृष्ठ हो सकते हैं, जिस स्थिति में यह केवल शिकायत का सार है जिसे सामान्य डायरी में दर्ज किया जाना है न कि पूरी शिकायत। यह इस सुझाव के अनुरूप नहीं है कि सामान्य डायरी में जो दर्ज किया गया है उसे एफआईआर दर्ज करने की धारा 154 की आवश्यकता के साथ पूर्ति/अनुपालन माना जाना चाहिए। वास्तव में, सामान्य प्रथा यह है कि एफआईआर बुक में पूरी शिकायत दर्ज की जाती है (या इसे एफआईआर फॉर्म के साथ संलग्न किया जाता है) लेकिन जनरल डायरी में केवल एक या दो पैराग्राफ (जानकारी का सार) दर्ज किया जाता है।

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

XXX XXX XXX

70. यदि संहिता की धारा 154 और पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 44 के प्रावधानों में इस तथ्य के संबंध में कोई असंगति है कि एफआईआर बुक में एफआईआर दर्ज की जानी है या सामान्य डायरी में, तो संहिता की धारा 154 के प्रावधान और पुलिस अधिनियम की धारा 44 के प्रावधान, 1861 (या संबंधित पुलिस अधिनियम या अन्य संबंधित राज्यों में नियमों के समान प्रावधान) प्रतिकूलता की सीमा तक शून्य होंगे। इस प्रकार, एफआईआर को एफआईआर बुक में दर्ज किया जाना है, जैसा कि संहिता की धारा 154 के तहत अनिवार्य है, और यह कहना सही नहीं है कि जानकारी पहले जनरल डायरी में दर्ज की जाएगी और प्रारंभिक जांच के बाद ही, यदि आवश्यक हो, तो सूचना एफआईआर के रूप में दर्ज की जाएगी।

XXX XXX XXX

72. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि एफआईआर का पंजीकरण अनिवार्य है और यह भी कि इसे प्रत्येक एफआईआर को एक अद्वितीय वार्षिक नंबर देकर एफआईआर बुक में दर्ज किया जाना है ताकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ सक्षम न्यायालय द्वारा प्रत्येक पंजीकृत एफआईआर की सख्त ट्रेकिंग को सक्षम किया जा सके, जिसमें प्रत्येक एफआईआर की प्रतियां भेजी जानी आवश्यक हैं।

XXX XXX XXX

97. संहिता दो प्रकार की एफआईआर पर विचार करती है: धारा 154 (1) के तहत विधिवत हस्ताक्षरित एफआईआर पुलिस स्टेशन में संबंधित अधिकारी को सूचनादाता द्वारा की जाती है। दूसरी तरह की एफआईआर वह हो सकती है जो पुलिस द्वारा प्राप्त

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

किसी भी सूचना पर या मुखबिर के अलावा अन्य [धारा 157 (1)] द्वारा दर्ज की जाती है और यहां तक कि इस जानकारी को विधिवत दर्ज किया जाना चाहिए और प्रति तुरंत मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए। संहिता की धारा 154 (1) के तहत या अन्यथा संहिता की धारा 157 (1) के तहत सूचनादाता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। एफआईआर दर्ज करने की बाध्यता के अंतर्निहित फायदे हैं:

97.1.(a) यह पीड़ित के लिए "न्याय तक पहुंच"का पहला कदम है।

97.2.(b) यह "कानून के शासन"को बरकरार रखता है क्योंकि साधारण व्यक्ति राज्य के ज्ञान में एक संज्ञेय अपराध के कृत्य को सामने लाता है।

97.3.(g) इससे त्वरित जांच-पड़ताल और कभी-कभी अपराध की रोकथाम भी हो जाती है। दोनों ही मामलों में, यह केवल कानून के शासन को प्रभावित करता है।

97.4.(घ) इससे आपराधिक मामलों में हेराफेरी कम होती है और पूर्व सूचना रिपोर्ट अथवा जानबूझकर विलंबित प्रथम सूचना रिपोर्ट की घटनाओं में कमी आती है।

(महत्त्व सन्निविष्ट)

राम चंदर बनाम हरियाणा राज्य, (1981) 3 एससीसी 191,

"3.... अदालत, अभियोजन और बचाव पक्ष को एक टीम के रूप में काम करना चाहिए जिसका लक्ष्य न्याय है, एक टीम जिसका कप्तान न्यायाधीश है। न्यायाधीश, 'एक गाना बजानेवालों के कंडक्टर की तरह, व्यक्तित्व के बल से, अपनी टीम को सद्भाव में काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए; कर्कश को वश में करो,

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

डरपोक को प्रोत्साहित करो, युवा के साथ साजिश करो, चापलूसी करो और (इस प्रकार) बूढ़े।

न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी

साक्ष्य अधिनियम की धारा 165

"165. प्रश्न पूछने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति--न्यायाधीश, सुसंगत तथ्यों का पता लगाने या उनका उचित प्रमाण प्राप्त करने के लिए, प्रासंगिक या असंगत किसी तथ्य के बारे में किसी गवाह से या पक्षकारों से किसी भी रूप में, किसी भी समय कोई प्रश्न पूछ सकेगा; और किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने का आदेश दे सकेगा; और न तो पक्षकार और न ही उनके एजेंट ऐसे किसी प्रश्न पर कोई आपत्ति करने के हकदार होंगे या आदेश, न ही, न्यायालय की अनुमति के बिना, ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी गवाह से प्रतिपरीक्षा करने के लिए:

बशर्ते कि निर्णय इस अधिनियम द्वारा घोषित तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, प्रासंगिक होने के लिए, और विधिवत साबित होना:

बशर्ते कि यह धारा किसी भी न्यायाधीश को किसी भी गवाह को किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर करने के लिए अधिकृत नहीं करेगी, या किसी भी दस्तावेज को पेश करने के लिए जो ऐसा गवाह धारा 121 से 131 के तहत जवाब देने या पेश करने से इनकार करने का हकदार होगा, दोनों समावेशी, यदि प्रश्न पूछा गया था या दस्तावेज प्रतिकूल पार्टी द्वारा मांगा गया था; न ही न्यायाधीश कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 148 या 149 के तहत पूछना अनुचित होगा; न ही वह किसी भी दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य को छोड़ देगा, सिवाय इसके पहले के मामलों को छोड़कर।

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

29. साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 मुकदमे के दौरान सवाल पूछने और दस्तावेजों को पेश करने का आदेश देने की अदालत की शक्ति की बात करती है। यह एक सामान्य और सर्वव्यापी शक्ति है जो सच्चाई की तलाश में अदालत को दी जाती है। इस तरह की शक्ति का प्रयोग इसके समक्ष किसी भी गवाह के खिलाफ किया जाना है, दोनों में एक सिविल और एक आपराधिक मामले में। उद्देश्य एक प्रासंगिक तथ्य के पर्याप्त प्रमाण की खोज करना है और इसलिए, उस उद्देश्य के लिए, न्यायाधीश को अपनी पसंद का कोई भी प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत और सशक्त किया गया है। जब अदालत द्वारा इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो कोई भी संबंधित अधिकार नहीं होता है जिसे किसी पक्ष द्वारा दिए गए प्रश्न के उत्तर में दिए गए उत्तर पर किसी गवाह से जिरह करने के लिए बढ़ाया जा सकता है, सिवाय उसकी अनुमति के। साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के महत्व पर जोर देते हुए, सर जेम्स स्टीफन ने साक्ष्य अधिनियम पारित करते समय प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा,

"यह नितांत आवश्यक है कि न्यायाधीश को न केवल वही सुनना चाहिए जो दूसरों द्वारा उसके सामने रखा गया है, बल्कि उसे अपनी जांच से यह पता लगाना चाहिए कि तथ्य वास्तव में कैसे खड़े हैं। ऐसा करने के लिए, उसके लिए अक्सर उन मामलों में जाना आवश्यक होगा जो स्वयं मुद्दे के मामलों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है, और यह न्यायाधीशों को ऐसा करने के लिए व्यक्त अधिकार के साथ सशस्त्र करने के लिए है कि धारा 165, जिस पर इतनी आपत्ति की गई है, निर्माण किया गया है"।

"भारत में एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को अक्सर उन कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है जो इंग्लैंड में पुलिस अधिकारी या वकीलों द्वारा किया जाएगा। उसे अपने लिए सच्चाई को बाहर निकालना होगा जितना वह कर सकता है, और एक पेशेवर प्रकार की थोड़ी सहायता के साथ। धारा 165 का उद्देश्य न्यायाधीश को सच्चाई तक पहुंचने के उद्देश्य से सबसे व्यापक शक्ति प्रदान

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

करना है। इस धारा का प्रभाव यह है कि गिनती से पहले मामले की तह तक जाने के लिए, वह हर तथ्य को देखने और पूछताछ करने में सक्षम होगा।

(महत्त्व सन्निविष्ट)

30. राम चंदर बनाम हरियाणा राज्य, (1981) 3 एससीसी 191,

"ओ. चिन्नप्पा रेड्डी, जे.- आपराधिक मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश की वास्तविक भूमिका क्या है? क्या उन्हें फुटबॉल मैच में रेफरी की भूमिका निभानी चाहिए या क्रिकेट मैच में अंपायर की भूमिका निभानी चाहिए, जैसा कि पोलक और मैटलैंड (पोलक एंड मैटलैंड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लॉ) ने उल्लेख किया है, प्रश्न यह कैसे है, या, क्या वह लॉर्ड डेनिंग के शब्दों में न्यायाधीश का पद छोड़ दें और एक अधिवक्ता का चोला धारण कर लें? [जोन्स वी। राष्ट्रीय कोयला बोर्ड, (1957) 2 ऑल ईआर 155: (1957) 2 डब्ल्यूएलआर 760] क्या वह परीक्षण में दर्शक या भागीदार होगा? क्या निष्क्रियता या गतिविधि उसके दृष्टिकोण को चिह्नित करने के लिए है? यदि वह किसी गवाह से पूछताछ करना चाहता है, तो वह कितनी दूर जा सकता है? क्या वह दस्ताने पहन सकता है और उस गवाह पर 'जा सकता है' जिस पर उसे संदेह है कि वह झूठ बोल रहा है या क्या वह नरम और सौम्य है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हम इस अपील में स्वयं से पूछने के लिए बाध्य हैं क्योंकि जिस प्रकार से इस मामले का विचारण करने वाले न्यायाधीश ने कुछ गवाहों से प्रश्न पूछे थे।

2. विचारण की प्रतिकूल प्रणाली यह है कि किसी विचारण की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश के लिए एक रेफरी या अंपायर की भूमिका ग्रहण करने और विचारण प्रक्रिया में प्रवेश करने वाले जुझारू और प्रतिस्पर्धी तत्वों से प्रवाहित होने वाली अपरिहार्य विकृतियों के साथ अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच एक

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)
प्रतियोगिता में विकसित होने की अनुमति देने की दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है। यदि एक आपराधिक अदालत को न्याय प्रदान करने में एक प्रभावी साधन बनना है, तो पीठासीन न्यायाधीश को एक दर्शक और केवल रिकॉर्डिंग मशीन नहीं रहना चाहिए। उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए गवाहों से सवाल पूछकर बुद्धिमान सक्रिय रुचि दिखाकर मुकदमे में भागीदार बनना चाहिए। जैसा कि हम में से एक को अतीत में कहने का अवसर मिला था:

हर आपराधिक मुकदमा खोज की एक यात्रा है जिसमें सत्य की खोज है। पीठासीन न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि वह सच्चाई का पता लगाने और न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए खुले हर रास्ते का पता लगाए। इस उद्देश्य के लिए उसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 द्वारा गवाहों से प्रश्न पूछने का अधिकार है। वास्तव में एक न्यायाधीश को दिया गया अधिकार इतना व्यापक है कि वह किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी गवाह से, या किसी भी तथ्य, प्रासंगिक या अप्रासंगिक के बारे में पार्टियों से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 (2) अदालत को किसी मामले में पुलिस-डायरी भेजने और मुकदमे में सहायता के लिए उनका उपयोग करने में सक्षम बनाती है। प्रतिबद्ध मजिस्ट्रेट की कार्यवाही के रिकॉर्ड को सत्र न्यायाधीश द्वारा परीक्षण में उसकी सहायता करने के लिए भी देखा जा सकता है। [सत्र न्यायाधीश, नेल्सोर बनाम भारत संघ इंथा रमण रेड्डी आईएलआर 1972 एपी 683: 1972 सीआरआई एलजे 1485]

3. इतनी व्यापक शक्तियों के साथ, अदालत को सच्चाई को उजागर करने और कमजोर और निर्दोष लोगों की रक्षा करने के लिए मुकदमे में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। निस्संदेह, प्रश्न

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

पूछने में अभियोजक की भूमिका नहीं माननी चाहिए। वकील के कार्यों, विशेष रूप से लोक अभियोजक के कार्यों, न्यायाधीश द्वारा हड़पने के लिए नहीं हैं, अखाड़े में उतरकर, जैसा कि यह था। न्यायाधीश द्वारा पूछा गया कोई भी प्रश्न ऐसा होना चाहिए ताकि गवाहों को डराया न जाए, मजबूर न किया जाए, भ्रमित न किया जाए या डराया न जाए। गवाहों के प्रति बहुत कठोर रवैया अपनाने वाले न्यायाधीश में निहित खतरे को लॉर्ड जस्टिस बिकेट द्वारा समझाया गया है:

अदालत की प्रक्रिया के आदी लोगों को पीठासीन न्यायाधीश से लंबे समय तक पूछताछ की परीक्षा के तहत अभिभूत या भयभीत, या भ्रमित, या व्यथित होने की संभावना है। इसके अलावा, जब पूछताछ एक व्यंग्यात्मक या विडंबनापूर्ण स्वर पर ले जाती है जैसा कि यह करने के लिए उपयुक्त है, या जब यह एक शत्रुतापूर्ण नोट पर ले जाता है जैसा कि कभी-कभी लगभग अपरिहार्य होता है, तो खतरा न केवल यह है कि गवाह सबूत पेश करने में असमर्थ होंगे जैसा कि वे चाहते हैं, लेकिन पार्टियां सोचना शुरू कर सकती हैं, काफी गलत तरीके से यह हो सकता है, कि न्यायाधीश अंततः न्याय के तराजू को धारण नहीं कर रहा है। [सुप्रा एफएन 2 में लॉर्ड डेनिंग द्वारा निकाला गया]

में जोन्स वी। राष्ट्रीय कोयला बोर्ड [जोन्स वी। नेशनल कोल बोर्ड, (1957) 2 ऑल ईआर 155: (1957) 2 डब्ल्यूएलआर 760] लॉर्ड जस्टिस डेनिंग ने देखा:

इस सब में न्यायाधीश का हिस्सा सबूतों को सुनना है, केवल खुद गवाहों के सवाल पूछना है जब किसी भी बिंदु को स्पष्ट करना आवश्यक है जिसे अनदेखा किया गया है या अस्पष्ट छोड़ दिया गया है; यह देखने के लिए कि अधिवक्ता स्वयं उचित व्यवहार करते हैं और कानून द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं;

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

अप्रासंगिकता को बाहर करने और पुनरावृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए; बुद्धिमान हस्तक्षेप द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह उन बिंदुओं का पालन करता है जो अधिवक्ता बना रहे हैं और उनके मूल्य का आकलन कर सकते हैं; और अंत में अपना मन बनाने के लिए कि सच्चाई कहां है। यदि वह इससे आगे जाता है, तो वह न्यायाधीश का पद छोड़ देता है और एक वकील की भूमिका ग्रहण करता है; और परिवर्तन उसे अच्छी तरह से नहीं बनता है।

हम लॉर्ड डेनिंग से आगे जा सकते हैं और कह सकते हैं कि सच्चाई की खोज करना एक न्यायाधीश का कर्तव्य है और इस उद्देश्य के लिए वह "किसी भी तथ्य, प्रासंगिक या अप्रासंगिक के बारे में किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी गवाह या पार्टियों से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है" (धारा 165 साक्ष्य अधिनियम)। लेकिन यह उसे लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील के कार्यों पर अनुचित रूप से अतिक्रमण किए बिना, पक्षपात के किसी भी संकेत के बिना और गवाहों को डराने या धमकाने के बिना करना चाहिए। उसे अभियोजन और बचाव पक्ष को अपने साथ ले जाना चाहिए। अदालत, अभियोजन और बचाव पक्ष को एक टीम के रूप में काम करना चाहिए जिसका लक्ष्य न्याय है, एक टीम जिसका कप्तान न्यायाधीश है। न्यायाधीश, 'एक गाना बजानेवालों के कंडक्टर की तरह, व्यक्तित्व के बल से, अपनी टीम को सद्भाव में काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए; कर्कश को वश में करो, डरपोक को प्रोत्साहित करो, युवा के साथ साजिश करो, चापलूसी करो और (इस प्रकार) बूढ़े।

(महत्त्व सन्निविष्ट)

तथ्यों पर

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

31. हमने परिस्थितियों, अभियुक्तों की उद्देश्य, भूमिका और अपीलकर्ता के अपराध को मुख्य रूप से सामने लाने के लिए अभियोजन पक्ष की इच्छा पर अपना विचार दिया है: (ए) मृत्यु पूर्व बयान, (बी) चश्मदीद गवाह, (सी) बरामदगी और (डी) अपराध के दृश्य के पास अपीलकर्ता की कथित गिरफ्तारी।
32. PW-5 से पहले PW-1 की उपस्थिति बेहद संदिग्ध है। उनकी उपस्थिति से PW -5 द्वारा बिल्कुल भी बात नहीं की गई थी। PW -1 का सबूत काफी अप्राकृतिक है क्योंकि उसने न तो सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में मकसद के बारे में बात की है, न ही तथाकथित मृत्यु पूर्व बयान के बारे में जो PW -5 द्वारा भी नहीं देखा गया था। PW-5 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक की हालत बहुत गंभीर थी, खून बह रहा था और इसलिए वह पर्याप्त उपचार नहीं दे सका। मृतक को आनन-फानन में दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। PW -1 को किसी श्री इंदर सिंह को शिकायत लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसकी अभियोजन पक्ष द्वारा उत्सुकता से जांच नहीं की गई है। किसी भी मामले में, PW -11 को एफआईआर दर्ज करने के लिए PW -1 के आने की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसे उन्हें अस्पताल से रिपोर्ट प्राप्त करते ही ऐसा करने के लिए अनिवार्य किया गया था। PW-1 की गवाही भी PW-3 और PW-8 की विरोधाभासी है।
33. इसी तर्ज पर, हम PW-2 और PW-3 के साक्ष्य पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं। PW -2 की जांच PW -11 द्वारा 2 सप्ताह से अधिक समय तक नहीं की गई थी, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस गवाह ने यह भी कहा कि वह मृतक का दोस्त नहीं था और इसलिए, घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति एक गंभीर संदेह पैदा करती है कि वह मृतक के साथ पिकनिक स्थल पर कैसे गया। PW-3, हालांकि मृतक के साथ था, उसके बाद उपस्थित नहीं था, जैसा कि PW-5 द्वारा गवाही दी गई थी और मृतक को PW-8 द्वारा दिए गए बयान के अनुसार दूसरे अस्पताल में भर्ती नहीं किया था। इसके विपरीत, PW -3 का सबूत यह है कि यह PW -1 है और खुद ने

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

मृतक को भर्ती किया है। इसके अलावा, उसके बाद भी उनकी उपस्थिति पर PW-5 द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था।

34. हालांकि हम कुछ हद तक PW -5 के साक्ष्य पर भरोसा करते हैं, लेकिन आपातकालीन चिकित्सा रजिस्टर पूरी तरह से उसके द्वारा नहीं भरा गया था। कोई भी इस बात का कारण नहीं जानता कि उन्होंने आंशिक रूप से रजिस्टर क्यों भरा और शेष हिस्सा डॉ. बीवी शर्मा द्वारा क्यों भरा गया, जिनकी अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था। आंशिक रूप से उनकी गवाही पर भरोसा करके, हम केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि उनके साक्ष्य अभियोजन पक्ष के संस्करण के खिलाफ दो मामलों में जाते हैं, अर्थात्, किसी अन्य गवाह की उपस्थिति और मृतक की स्थिति।
35. अभियोजन पक्ष ने वाहन के चालक यानी उस टेम्पो की जांच करने का विकल्प नहीं चुना है जिसमें मृतक को अस्पताल ले जाया गया था। यहां तक कि PW -5 ने भी कहा है कि मृतक के शरीर से खून निकल रहा था। इस संबंध में PW-2 और PW-3 के कथन में यह एक और विरोधाभास है। PW -8 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि मृतक को मृतक का दूसरा भाई लेकर आया था। यहां तक कि अभियोजन पक्ष को ज्ञात कारण के लिए इस गवाह से भी पूछताछ नहीं की गई है।
36. PW-9 एक महत्वपूर्ण गवाह है जो एक अलग अधिकार क्षेत्र से आने वाला एक पुलिस अधिकारी है। यह जानना बहुत उत्सुक है कि PW -11 द्वारा जांच किए जाने के बाद वह पूछताछ रिपोर्ट के लेखक थे। यह बहुत अजीब होने के बावजूद, उसकी ओर से कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं आ रहा था। हालांकि PW-11 यह कहने की कोशिश कर रहा था कि कई बार उच्च अधिकारियों के निर्देशों के कारण, ऐसा किया जाता है, जब कोई अपराध किया जाता है तो एक विवेचना अधिकारी विवेचना करने और इसे पूरा करने के लिए बाध्य होता है। विवेचना शुरू करने के बाद वह उचित कारणों को छोड़कर इसे प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है। यह बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए मामले को विश्वसनीयता देता है कि केस डायरी में इंटरपोलेशन और

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

लापता पृष्ठ स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि एफआईआर पूर्व-दिनांकित थी। शायद यही कारण है कि एफआईआर देर से न्यायिक मजिस्ट्रेट तक पहुंची और सीआरपीसी की धारा 161 के तहत PW -2 सहित गवाहों की विवेचना भी घटना के कुछ दिनों बाद की गई।

37. PW-6 और PW-7 प्राकृतिक गवाह नहीं हैं। PW-6 के लिए जिज्ञासा से घटना स्थल तक पहुंचना पूरी तरह से अविश्वसनीय है। उसे उसी स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। PW -7 के इशारे पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियोजन पक्ष द्वारा मामला बनाने की कोशिश का एक और उदाहरण है। यह समझ से बाहर है कि अपीलकर्ता घटना के स्थान पर मौजूद होगा जब वह भागने का प्रयास कर रहा होगा। इसी तरह का तर्क चाकू की बरामदगी के लिए जाता है। यदि PW -11 को एक निरीक्षण करने और स्केच तैयार करने के लिए कहा जाता है, तो उसे पास के स्थान पर चाकू बहुत अच्छी तरह से मिल गया होगा। यह किसी का मामला नहीं है कि यह छिपा हुआ था, इसके विपरीत, यह एक खुली जगह में पाया गया था।
38. उपरोक्त चर्चा से, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि घटना की तारीख, समय और स्थान भिन्न हो सकते थे। ट्रायल कोर्ट ने गायब पन्नों के साथ-साथ केस डायरी में किए गए सुधारों के संबंध में भी अपीलकर्ता पर जिम्मेदारी डाल दी। केस डायरी के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि कई स्थानों पर इस तरह के सुधार किए गए हैं, जबकि कुछ पृष्ठ भी गायब थे। तारीखों को सही करने का स्पष्ट प्रयास किया जाता है। इस तरह के सुधार वास्तव में अपीलकर्ता के खिलाफ किए गए थे, जबकि उन्होंने वास्तव में अभियोजन पक्ष के मामले में मदद की थी। इस संबंध में ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष न तो तार्किक है और न ही उचित है। मकसद के सवाल पर भी, बिल्कुल कोई सामग्री नहीं है क्योंकि गवाहों ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयानों में इसके बारे में बात नहीं की। केवल एक मोटरसाइकिल की बरामदगी अभियोजन पक्ष के मामले को साबित नहीं करेगी, खासकर जब यह साबित नहीं हुआ है कि इसे कैसे बरामद किया गया था। PW -13 के

शैलेश कुमार वि. उत्तर प्रदेश राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि केस डायरी में कोई तारीख, समय और उचित रिकॉर्डिंग नहीं की गई है। जब ट्रायल कोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी के बयान का खंडन करने के उद्देश्य से केस डायरी का अवलोकन किया, तो उसे अपीलकर्ता पर जिम्मेदारी तय नहीं करनी चाहिए थी। यह सीआरपीसी की धारा 172 (3) के साथ धारा 145 या धारा 161, जैसा भी मामला हो, साक्ष्य अधिनियम के तहत निहित अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है। ध्यान दिया जाना चाहिए, यह अपीलकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर लाया गया था और अदालत विरोधाभास के उद्देश्य से इसका उपयोग कर रही थी।

39. अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में आक्षेपित निर्णय और ट्रायल कोर्ट के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि हमारे द्वारा चर्चा किए गए पहलुओं को उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया है। अपीलकर्ता ने निश्चित रूप से बरी होने का मामला बनाया है। तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि, ट्रायल कोर्ट की पुष्टि करती है, को रद्द कर दिया जाता है। अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी किया जाता है।
40. अपील की अनुमति दी जाती है। अपीलकर्ता को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06.04.2015 द्वारा जमानत दी गई थी। इसलिए जमानत बांड जारी किए जाते हैं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट्स: अंकित ज्ञान

मामले का परिणाम:

अपील की अनुमति दी।